mills in the Cooperative Sector in Gujarat are as under:—

(1) The Narmada Rao Utpadakani Sahakari Spinning Mills Ltd., Distt. Bharuch.

(2) The Sabarkantha Jilla Ru Utpadakani Cooperative Spinning Mills Ltd., Distt. Sabarkantha.

(3) Saurashtra Cooperative Spinning Mills Ltd., Limbdi Surendra Nagar Distt.

(4) The Surat Distt. Cooperative Spinning Mills Ltd., Distt. Surat.

(5) The Visnagar Cooperative Spinning Mills Ltd., Visanagar Distt. Mehsana (North Gujarat).

(c) Government of Gujarat has not proposed setting up of any new mills during the next year.

Slump in silk saree industry

*478. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a slump in the silk saree industry in the country;

(b) whether it is also a fact that the condition of weavers engaged in the industry is miserable;

(c) if so, the reasons thereof; and

(d) what steps Government propose to take to arrest the slump in the industry and improve the condition of weavers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (d) While off-take of silk items is subject to seasonal variations, there are no reports with Central Government about adverse conditions of the weavers.

A number of Schemes are being implemented for providing different types of assistance to the weavers (including silk weavers) for ameliorating their conditions. Further, in order to encourage/boost the silk production in the country, the Central Silk Board is supplementing the efforts of various State Governments by providing necessary support through its country-wide network of research, extension & training units. Besides a World Bank assisted National Sericulture Project is also under implementation.

Further, with a view to make available quality silk yarn to the weavers at stable prices, Government has introduced a National Silk Yarn Bank Scheme from 1992-93 to be implemented, to begin with, in the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and the North Eastern States.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उद्देश्य

*479. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अब उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नौकरशाहों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनके अविवेक पूर्ण निर्णयों के कारण इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निगमित करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत रुग्ण वस्त्र उपक्रमों के मामलों की देखरेख करना था यह भी प्रस्ताव था कि इन मिलों को आर्थिक रुप से अर्थक्षम बनाने के लिये

इनका पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण किया जाए। फिलहाल एन टी सी द्वारा 109 राष्ट्रीयकृत और 15 प्रबन्धित मिलों का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि एन टी सी इन मिलों को चलाने में सक्षम रही है फिर भी पुरानी एवं अप्रचलित मशीनरी, फालतू श्रमिक बल, अपर्याप्त आधुनिकीकरण और अशतः कार्य पद्धति के कारण भी इन मिलों को आर्थिक रूप से अर्धक्षम बनाना संभव नहीं हो पाया है।

राजस्थान में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

†480. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या **वस्त्र** मंत्री 27 अप्रैल 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 63 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हुई हैं ; और उनमें से कितनी राजस्थान में हैं ;

(ख) क्या सरकार इन मिलों को पुनः चालू करेगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कपड़ा मिलें लगाई गई अथवा निकट भविष्य में वहां कितनी कपड़ा मिलें लगाये जाने की योजना है;

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थान में कपास के उत्पादन का पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त मिलें नहीं है यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या राजस्थान के केवल कपास उत्पादन क्षेत्रों में ही मिल स्थापित करने की कोई योजना है यदि हां तो किन-किन स्थानों पर ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) 31 मई 1992 की स्थिति अनुसार देश में 134 सूती मानव निर्मित वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थी और इनमें 5 मिलें राजस्थान में हैं।।

(ख) किसी बन्द पड़ी मिल का दुबारा खुलना नोडिए अभिकरण। वो आई एफ आर के सामने स्थापित उसकी अर्थक्षमता पर निर्भर करता है। जोकि मिल की जांच पडताल करता है और अर्थक्षम मिलों के बारे में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करता है और उनका प्रबंध करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर राजस्थान में एक एकीकृत सहकारी कताई मिल की स्थापना की गई है।

(घ) राजस्थान की कपास का प्रयोग राजस्थान की मिलों के अलावा पूरे दे की किलों द्वारा किया जाता हैं।

(ङ) सरकार स्वयं किसी वस्त्र मिलें की स्थापना नहीं करती है, नहीं औद्योगिक नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मिल की स्थापना के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

D.R.D.O. Plant to desalinate brackish Water

3522. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a plant based on principle of reverse osmosis has been designed and fabricated by the DRDO to desalinate brackish water and decontaminate it from various types of chemicals; and

(b) if so, what are the details thereof including the cost of operating such a plant?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Yes, Sir.

(b) The plant has capacity to purify 7000 litres per hour of brackish water or 2000 litres per hour for